International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 27-07-2021, Accepted: 13-08-2021, Published: 28-08-2021
Volume 7, Issue 4, 2021, Page No. 156-157

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल' का जीवंत दृष्टांतः राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020

अर्चना शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
प्रस्तुत शोध–आलेख का ध्येय "राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020" के सन्दर्भ में व्यापक प्रकाश डालना रहा है । इस शोध–आलेख के माध्यम से "राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020" में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता एवं महत्त्व को आलोकित किया गया है । वर्तमान समय में "राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020" की रोज़गारोन्मुखी दृष्टि एवं प्रासंगिकता का महत्व प्रतिपादित करना शोध–आलेख की प्राथमिकता है।

मूल शब्दः राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, National Policy on Education (NPE) भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, ओ०डी०एल० मोड, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

प्रस्तावना

मेरा स्पष्ट मत है कि शिक्षा अज्ञानता के शोधन की प्रगतिशील खोज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 इस दिशा में एक सार्थक क़दम है। इस सार्थक और व्यावहारिक शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली ने लगभग 34 वर्ष पश्चात् (National Policy on Education (NPE) 1986) सकारात्मक करवट ली है। इसके माध्यम से पुनः विश्व गुरु भारत के ध्येय हेतु शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्वों के पक्ष से होकर अग्रसरित होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 विश्वविद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक और रोज़गारपरक शिक्षा का नवीन स्वरूप पुख़्ता करेगी। अभी तब जो शिक्षा नीतियाँ रही हैं, उनमें संज्ञानात्मक कौशल के विकास एवं सीखने के परिणामों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। यह प्रमुख कारण भी रहा कि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त छात्र नौकरी खोजने के अतिरिक्त अन्य कौशलों पर विचार ही न कर सका। स्वयं का छोटा–सा व्यवसाय अथवा उद्योग शुरू करने हेतु भी उसकी ज्ञान–गागर छोटी पड़ गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक भ्रम की स्थिति का जन्म हुआ जिसने जीवन–व्यवहार एवं पुस्तकीय ज्ञान को अलग–अलग करके देखने का चश्मा ईज़ाद कर दिया। किंतु मेरी दृष्टि में यह आदर्श स्थिति कदापि नहीं हो सकती। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का एक दृष्टांत देखिए –

यदि कोई छात्र कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर करता है, तो उसे साथ में प्रबंधन पर आधारित विषय मार्केटिंग अथवा एकाउंटिक नहीं पढ़ाया जाता, इसके कारण उसे स्वयं का उद्योग आरंभ करने हेतु प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। अंततः वह थक–हारकर कंप्यूटर संदर्भित नौकरी ही ढूंढ़ता–फिरता रहता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 में यह बदलाव किया गया है कि विश्वविद्यालयी स्तर पर बहु–विषयक स्नातक स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे विश्वविद्यालयी छात्र को आत्मनिर्भर और रोज़गार के लिए बहुआयामी अवसर उपलब्ध हों।

इसमें मात्र भाषिक स्तर पर प्रोत्साहन ही नहीं अनुवाद के स्तर पर बहुआयामी समाज को कुटुंब रूप में एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' (Indian Institute of Translation and Interpretation & IITI) के पार्श्व में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास का ध्येय कार्यरत है।

इस दिशा में फ़ारसी, पाली और प्राकृत हेतु राष्ट्रीय संस्थान (National Institute (or Institutes) for Pali) Persian and Prakrit) की निर्मिति भी अनुवाद–कर्म को प्रोत्साहित करेगी।

यदि ग़ौर करें तो स्मरण होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट रूप से सामने आया था कि प्रगत देशों की तुलना से, भारत में औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय बहुत अल्प हैं। मात्र 19–24 आयु वर्ग के मात्र 5 फीसदी से भी कम छात्र मौजूद हैं। इसका मुख्य कारण है कि कक्षा 11वीं तथा 12वीं के पश्चात् व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले छात्रों के सम्मुख अवसरों की उपलब्धता का खाँका मौजूद ही नहीं होता। इसे दूर करने हेतु 2013 में 'राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क' (NSQF) की घोषणा के माध्यम से कुछ छुटपुट प्रयास अवश्य किए गए थे।

अक्सर व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कमतर आंका जाता है। इस कारण बुद्धिमान छात्र व्यावसायिक शिक्षा के अधिगम को अपेक्षाकृत कम महत्त्व देता है। उसे प्रायः अंतिम स्थान पर रखता है। वह मानकर चलता है कि 'शारीरिक श्रम का महत्त्व' अधिक नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 में अंकित है कि विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीक़े से व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा की शिक्षा पर रूपांतरित करेंगे। इसमें यह सुनिश्चित होग कि प्रत्येक छात्र कम–से–कम एक व्यावसाय से परिचय अवश्य करेगा। इससे छात्र भारतीय कला एवं कारीगरी सहित अनेक व्यावसायों के महत्त्व को जान सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 का आगामी लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम–से–कम 50 फीसदी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक क्षमताओं के विकास के साथ–साथ छात्र का 'अकादमिक' विकास भी संभव हो सकेगा। इस हेतु उद्योग जगत् और गैर–सरकारी संगठनों सहित साझेदारी प्रमुख क़दम साबित होगा।

इसके साथ–साथ ओ०डी०एल० मोड के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप – महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा चरखा और हथकरघा के माध्यम से खादी कपड़ा उत्पादन का एडवांस डिप्लोमा शुरू करने का प्रयास किया गया है। मैं इसे सराहनीय क़दम मानती हूं।

वंचित तबकों के छात्रों हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति 'मुक्त दूरस्थ शिक्षा' ऑनलाइन कोर्स द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए

समस्त बुनियादी ढाँचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी।

नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजूकेशन (NCIVE) का गठन किया जाएगा जिसके माध्यम से शिक्षा के बहुआयामी विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि स्टार्ट–अप, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र हेतु उद्योगों से संतुलित जुड़ाव संभव हो तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NS QF) को प्रत्येक विषय व्यवसाय/रोजगार के लिए अधिक विस्तारपूर्वक निर्मित किया जाए और भारतीय मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाए।

प्रौद्योगिकी और शिक्षा के मध्य अंतर–विरोध नहीं अपितु द्विदिश (Bi&Directional) संबंध है। तकनीक को समझने एवं इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों की संख्या निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है। उद्यमिता का चक्का इसे अधिक द्रुत गति प्रदान करेगा।

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंम्यूटिंग उपकरण, छात्रों के विकास के लिए एडेप्टिव कम्यूटिंक टेस्टिंग और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर्स द्वारा जाना जा सकेगा कि छात्र क्या सीखता है तथा कैसे सीखता है। इस दृष्टि से भविष्य में विश्वविद्यालयी स्तर पर प्रौद्योगिकी और शैक्षिक स्तरों पर अधिक व्यापक शोध की आवश्यकता होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, नियेाजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा विचारों के मुक्त प्रवाह को मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) का निर्माण सार्थक क़दम साबित होगा।

निष्कर्ष

अस्तु, राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के माध्यम से भाषा–शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी का अद्भुत सामंजस्य स्थापित होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में भाषिक शक्ति के मेल से भारतीय भाषाओं की राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय सार्थकता प्रतिष्ठापित होगी। 'गूगल' (Google) द्वारा भारत के साथ भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं के आरंभ एवं विभिन्न भाषाओं में अनुवाद की तकनीकी उपलब्धता मुहैया कराने का प्रयास हो अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के तहत 'राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन' की स्थापना का स्वप्न समस्त प्रयास निश्चित ही सराहनीय क़दम हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्व पटल पर विश्व गुरु भारत पुनः दिनकर–सा आलोकित होगा .....।

संदर्भ सुची

1. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
4. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
5. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
6. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
7. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार